



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3—फरवरी 9, 2018 (माघ 14, 1939)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3—FEBRUARY 9, 2018 (MAGHA 14, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

बैंक ऑफ इंडिया

दिनांक 12 सितम्बर 2017

एफ. नं. BOI/HO/HR/IR/MSS/L-234—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 के साथ धारा 12 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बना रहा है, अर्थात:—

1. (1) इन विनियमों को बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमन, 2017 कहा जाएगा।
(2) इन विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोड़कर, ये विनियम 1 नवंबर, 2007 से लागू माने जाएंगे।
2. बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 (इसके बाद विनियमन कहा जाएगा) में, विनियम 3 में:—
(i) खण्ड (एफ) के लिए, उसके स्थान पर निम्नानुसार लिखा जाए, अर्थात:—

‘(एफ) “परिवार” से तात्पर्य है अधिकारी की पत्नी/पति, पूर्णतः निर्भर अविवाहित पुत्र/पुत्री (सौतेले और गोद लिए गए शामिल), चालीस प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन और माता-पिता जो सामान्यतः अधिकारी के साथ निवास करते हों और अधिकारी पर पूर्णतः निर्भर हों।’

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजन हेतु, कोई पुत्र/पुत्री या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन अधिकारी पर पूर्णतः निर्भर माने जाएंगे यदि ऐसे पुत्र/पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन की मासिक आय रु. 3,500/- प्रति माह से अधिक न हो। यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु. 3,500/- प्रतिमाह से अधिक हो या दोनों की कुल मासिक आय रु. 3,500/- प्रति माह से अधिक हो, तो दोनों को अधिकारी पर पूर्णतः निर्भर नहीं माना जाएगा।'

(ii) खण्ड (ओ) को हटा दिया जाएगा है।

3. कथित विनियम के विनियम 4 में :-

(i) उप-विनियम (4ए) हटा दिया जाएगा;

(ii) उपर्युक्तानुसार उप-विनियम (4ए) को हटाने के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा; यथा :—

“(5) 1 नवंबर 2007 से प्रभावी होते हुए; प्रत्येक ग्रेड के लिए निर्धारित वेतनमान निम्नानुसार होगा:—

(ए) उच्च कार्यपालक ग्रेड

वेतनमान VII = रु. 46800-1300/4-52000

वेतनमान VI= रु. 42000-1200/4-46800

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान V = रु. 36200-1000/2-38200-1100/2-40400

वेतनमान IV= रु. 30600-900/4-34200-1000/2-36200

(सी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान III = रु. 25700-800/5-29700-900/2-31500

वेतनमान II = रु. 19400-700/1-20100-800/10-28100

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान I = रु. 14500-600/7-18700-700/2 -20100-800/7 - 25700

स्पष्टीकरण—प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2007 को लागू वेतनमान द्वारा शासित हैं उन्हें 1 नवंबर, 2007 को इस उप-विनियम में दिए गए वेतनमान में स्टेज-से-स्टेज आधार पर फिट किया जाएगा, अर्थात् पहली स्टेज से संबंधित वेतनमान में समनुरूप वेतनमान में फिट किया जाएगा और हमेशा की तरह वर्षगांठ तारीख पर वेतनवृद्धि देय होगी जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) में किसी भी बात का यह आशय नहीं होगा कि बैंक में हर समय, इन सभी ग्रेड में अधिकारी सेवारत होना अपेक्षित है।”

4. कथित विनियमों के विनियम 5 में, -

(ए) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम, के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम होगा, अर्थात्:—

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अध्यधीन, 1 नवंबर, 2007 को और से, निम्नलिखित के अध्यधीन वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:—

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में उल्लिखित वेतनमानों में निर्धारित वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की शर्त के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर मिलेंगी और जिस महीने में वेतनवृद्धि देय होगी उस माह की पहली तारीख को प्रदान की जाएंगी;

(बी) कनिष्ठ प्रबंधन वेतनमान-I में अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के बाद मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-II के वेतनमान में आ गए हैं, वे प्रत्येक तीन-वर्ष-सेवापूर्ति हेतु चार स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे; इनमें से पहली दो वेतनवृद्धि प्रत्येक रु. 800/- की और अगली दो प्रत्येक रु. 900/- की होंगी:

बशर्ते जिन अधिकारियों ने यथा 1 नवंबर, 2007 को दूसरी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हों उन्हें 1 नवंबर, 2007 को तीसरी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि मिलेगी और दूसरी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा छः वर्ष पूरी करने पर 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद एक और स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि मिलेगी;

(सी) मध्य प्रबंधन वेतनमान स्केल-II में अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के बाद मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-III के वेतनमान में आ गए हैं, वे प्रत्येक तीन वर्ष सेवापूर्ति हेतु प्रत्येक रु.900/- के तीन स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे:

बशर्ते जिन अधिकारियों ने यथा 1 नवंबर, 2007 को पहली स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद तीन या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हों उन्हें 1 नवंबर, 2007 को पहली स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि मिलेगी और पहली स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा छः वर्ष पूरी करने पर 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद एक और स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि मिलेगी:

बशर्ते कि मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-III में नियुक्त या पदोन्नत किए गए अधिकारी प्रत्येक तीन वर्ष-सेवापूर्ति हेतु प्रत्येक रु. 900/- के चार स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे या;

बशर्ते जिन अधिकारियों ने पहले ही दो स्टैग्नेशन वेतन वृद्धि प्राप्त कर ली हो और यथा 1 नवंबर, 2007 को दूसरी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद पूरे कर लिए हों उन्हें 1 नवंबर, 2007 को तीसरी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि मिलेगी और दूसरी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा छः वर्ष पूरी करने पर 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद चौथी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि मिलेगी।

स्पष्टीकरण—इस उप-विनियम के तहत अगले वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियों को प्रदान किए जाने से पदोन्नति नहीं हो जाएगी और उन्हें प्राप्त विशेष सुविधाएं, अनुलाभ तथा उनके कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां उनके वास्तविक पद के अनुरूप जारी रहेंगी।

(बी) उप-विनियम (2) में,—

(i) स्पष्टीकरण में, खण्ड (ई) के बाद और नोट से पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

“(एफ) 1 नवंबर, 2007 को और से, अन्य चीज़ें बराबर होने पर, व्यावसायिक अर्हता वेतन (पीक्यूपी) की प्रमात्रा निम्नानुसार संशोधित होगी:—

तालिका

जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स पास कर लिया है।	(i) वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष बाद रु. 410/- प्रति माह।
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के दोनों भाग पास किया है।	(i) वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष बाद रु. 410/- प्रति माह। (ii) वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के दो वर्ष बाद रु. 1030/- प्रति माह;

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के पश्चात जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स (इनमें से कोई एक या दोनों भाग) की अर्हता प्राप्त करता है, तो ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख से, उसे व्यावसायिक अर्हता वेतन (पीक्यूपी) की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और पीक्यूपी की बाद की किस्तें, पीक्यूपी की पहली किस्त जारी करने की तारीख के संदर्भ में, जारी की जाएंगी;

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी, पहले ही उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई एक प्राप्त कर चुका है और ऐसी अर्हता प्राप्त करने हेतु उसे कोई वेतनवृद्धि या पीक्यूपी नहीं मिली है, तो उसे 1 नवंबर, 2007 या ऐसी अर्हता प्राप्ति की तारीख, इनमें से जो बाद में हो, से व्यावसायिक अर्हता वेतन (पीक्यूपी) प्रदान किया जा सकता है।”;

(ii) खण्ड (v) हेतु, नोट में, निम्नलिखित खण्डों को बदला जाएगा, यथा:-

“(v) यदि यथा 27 अप्रैल, 2010 कोई अधिकारी, पहले ही खण्ड (iv) में उल्लिखित कथित अर्हताएं प्राप्त कर चुका हो और ऐसी अर्हता प्राप्त करने हेतु उसे कोई वेतन वृद्धि या पीक्यूपी नहीं मिली हो, तो उसे 1 नवंबर 2007 या ऐसी अर्हता प्राप्ति की तारीख, इनमें से जो बाद में हो, से व्यावसायिक अर्हता वेतन (पीक्यूपी) प्रदान की जाएगी।”

(सी) उपनियम (3) में, -

(i) खण्ड (डी) के बाद तथा नोट से पूर्व निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा, जो इस प्रकार है:—

“01 नवंबर, 2007 को तथा उक्त तारीख से सभी चीजों के समान रहने पर आवास किराया भत्ता सहित स्थिर व्यक्तिगत वेतन निम्नलिखित दर पर होगा तथा पूरी सेवा अवधि के लिए अवरुद्ध रहेगा :-

तालिका

वेतनवृद्धि अंश (रु.)	वेतनवृद्धि अंश पर 01.11.2007 को महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक ने आवास सुविधा दी है, वहां कुल स्थिर व्यक्तिगत वेतन (एफपीपी) देय
(क)	(ख)	(ग)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394

(ii) खण्ड(i) तथा (ii) के लिए नोट में निम्नलिखित खण्डों को बदला जायेगा जो इस प्रकार है :—

“(i) स्थिर व्यक्तिगत भत्ता (एफपीपी) या स्थिर व्यक्तिगत वेतन (एफपीपी) जैसा कि तालिका के कॉलम सी के अंतर्गत खण्ड (बी), (सी) (डी) या (ई) में दर्शाया गया है, उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ता के लिए पात्र अधिकारियों के लिए स्थिर व्यक्तिगत भत्ता या स्थिर व्यक्तिगत वेतन तालिका के कॉलम ए तथा बी के खण्ड(ई) के अनुसार प्रतिपादित कुल राशि तथा संबंधित कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया आवास किराया भत्ता जब विनियमन 4 के उप-विनियम(2) (3) (4) (5) में उक्त संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त की जानी है, वह होगी।

(iii) नोट के बाद आने वाले खण्ड (ई) को दोबारा से खण्ड (V) की संख्या दी जायेगी तथा निम्नलिखित को इस प्रकार से बदला जायेगा:—

“ (v) उपर्युक्त खण्ड (ए) के अनुसार जिस अधिकारी ने अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त की है, वह वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद उपर्युक्त खण्ड (बी),(सी), (डी) या (ई) में जैसा उल्लिखित है, स्थिर व्यक्तिगत भत्ता/स्थिर व्यक्तिगत वेतन प्राप्त करेंगे”;

5. कथित विनियमों के विनियम 21 में, -

(i) उप-विनियम (3) में नोट हटा दिया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (4) में नोट हटा दिया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (4) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम तथा नोट जोड़ा जायेगा जो इस प्रकार है:—

“ (5) 01 नवंबर 2007 को तथा उक्त तारीख से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 अंकों में प्रत्येक चार अंक की वृद्धि या कमी पर महंगाई भत्ता देय होगा। (सामान्य) आधार वर्ष 1960=100, वेतन के 0.15% के दर से।

व्याख्या—इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए, -

(ए) महंगाई भत्ता के उद्देश्य के लिए “वेतन” का अर्थ है स्टैगनेशन वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन,

(बी) जैसा कि विनियम 5 के उप-विनियम (2) की व्याख्या (सी) (डी) (ई) तथा (एफ) में विनिर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता (पीक्यूए) या व्यावसायिक योग्यता वेतन (पीक्यूपी) महंगाई भत्ते के योग्य होगी।

6. उक्त विनियमन के विनियम 22 में उप-विनियम (1) तथा (2) के लिए निम्न उप-विनियम को बदला जायेगा जो इस प्रकार है:—

“ (1) 01 नवंबर 2002 को तथा उक्त तारीख से,

- (ए) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवास सुविधा दी गयी है, अधिकारी जिस वेतनमान में हो उसके प्रथम चरण के मूल वेतन का 1.75 प्रतिशत या आवास का मानक किराया जो भी कम हो, वह राशि उससे वसूली जायेगी।
- (बी) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा नहीं दी गयी है, वहां निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दर पर वह आवास किराया भत्ते हेतु पात्र होगा, जो इस प्रकार है:

तालिका

जहां कार्य स्थल निम्न में है	देय एच.आर.ए होगा
(1)	(2)
(i) मेज़र "ए" श्रेणी के शहर तथा समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन को 6.5%

परन्तु यदि अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए की वास्तविक राशि में से, वह जिस वेतनमान में हो उसके प्रथम चरण के वेतन का 1.75% घटाकर शेष बची राशि, उसे देय एचआरए होगी। तथापि उसे देय अधिकतम एचआरए, उपर्युक्त कॉलम (2) के अनुरूप एचआरए का 150% होगी।

(2) 01 नवंबर 2007 को तथा उक्त दिन से, -

- (ए) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवास सुविधा दी गयी है, वहां वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम चरण के मूल वेतन का 1.20 प्रतिशत या आवास का मानक किराया जो भी कम हो, वह राशि उससे वसूली जायेगी।
- (बी) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा नहीं दी गयी है, वहां निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दर पर वह आवास किराया भत्ता हेतु पात्र होगा जो इस प्रकार है:-

तालिका

जहां कार्य स्थल निम्न में है	देय एच.आर.ए होगा
(1)	(2)
(i) बड़े "ए" श्रेणी के शहर तथा समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन को 6.5%

परन्तु यदि अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए की वास्तविक राशि में से, वह जिस वेतनमान में हो उसके प्रथम चरण के वेतन का 1.20% घटाकर शेष बची राशि, उसे देय एचआरए होगी। तथापि उसे देय अधिकतम एचआरए, उपर्युक्त कॉलम (2) के अनुरूप एचआरए का 150% होगी।

नोट : अधिकारियों के स्वामित्व के आवास की लागत से संबंध मकान किराया भत्ते हेतु उनका दावा, पहले की तरह एचआरए के 150% तक सीमित रहेगा।

7. उक्त विनियम के विनियम 23 के अनुसार, -

- (i) उप-विनियम (i) में संख्या, अक्षर तथा शब्द "1 नवंबर 2002," के स्थान पर संख्या अक्षर तथा शब्द "1 नवंबर 2007" लिखा जाएगा;
- (ii) उप-विनियम (2) में संख्या, अक्षर तथा शब्द "1 नवंबर 2002 का प्रथम दिन," के स्थान पर संख्या अक्षर तथा शब्द "1 नवंबर 2007" लिखा जाएगा;
- (iii) उप-विनियम (3), (4), (5) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम बदले जायेंगे जो इस प्रकार हैं:—

" (3) 01 नवम्बर 2007 को तथा उक्त तारीख से यदि कोई अधिकारी समूह ए तथा समूह बी में परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्धारित किये जा रहे क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो वह समूह ए तथा समूह बी के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः रु. 290 या रु. 255 की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते का पात्र होगा।

- (4) 01 नवंबर 2007 को तथा उस दिन से यदि कोई अधिकारी अकादमिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरित होता है तथा पूर्व के स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिस तारीख से वे नये स्थान पर रिपोर्ट करते हैं, उस तारीख से, तो सभी बच्चों के सम्बन्ध में अकादमिक वर्ष की समाप्ति तक रु.700 का मध्य अकादमिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्त होगा, परन्तु यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना छोड़ देते हैं तो वैसा भत्ता बंद हो जायेगा।
- (5) 01 मई 2010 को या उस तारीख से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे जिस पद पर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है वह उससे संबंधित परिलब्धियां प्राप्त कर सकता है या वह अपने वेतन के अतिरिक्त अपने वेतन का 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्त भत्ता जो अधिकतम रु. 2300 प्रतिमाह होगा तथा वैसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है जो उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर उसे प्राप्त होते।

परन्तु यदि वह ऐसी संस्था में प्रतिनियुक्त होता है जो उस जगह स्थित है जहाँ वह प्रतिनियुक्त के ठीक पूर्व तैनात था तो उसे वेतन का 4 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा परन्तु यह भत्ता अधिकतम प्रति माह रु.1200 होगा।

इसके अतिरिक्त यदि अधिकारी को संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह वेतन के 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते हेतु पात्र होगा परन्तु यह भत्ता अधिकतम प्रतिमाह रु.1200 होगा।

(iv) उप-विनियम (8) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम बदले जायेंगे जो इस प्रकार हैं-

"(8) 01 नवंबर 2007 को तथा उक्त तारीख से यदि दिन में न्यूनतम दो घंटे के अंतराल सहित कार्यालयीन समय बांटा जाता है तो वह अधिकारी प्रतिमाह रु.165 की दर से विभक्त सेवा भत्ते (Split Duty Allowance) हेतु पात्र होगा।"

(v) विनियम (10) में -

(ए) संख्या, अक्षर और शब्द "1 नवंबर 2002" के बदले लिए संख्या, अक्षर और शब्द "1 नवंबर 2007" लिखा जाएगा।

(बी) तालिका के स्थान पर, निम्न तालिका होगी, अर्थात:

"तालिका"

स्थान (1)	दर (2)
(i) 1000 मीटर से अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान और मर्काला कस्बा	वेतन का 2% अधिकतम रु. 550 प्रतिमाह
(ii) 1500 मीटर से अधिक किन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2 ^{1/2} % अधिकतम रु. 680 प्रतिमाह
(iii) 3000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु. 1570 प्रतिमाह

8. कथित विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) में, खंड(ए) के बदले निम्नलिखित खंड होगा, अर्थात :-

"(ए) चिकित्सा व्यय (Medical expenses) : 1 नवंबर 2007 को और उसके पश्चात कोई अधिकारी स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, यदि ऐसे व्यय को स्वयं प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित करता है और नीचे तालिका में निर्धारित अनुसार दावा की गयी राशियों के लिए विवरण प्रस्तुत करता है, यथा:

"तालिका"

ग्रेड (1)	प्रतिपूर्ति की उच्चतम सीमा (2)
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन ग्रेड	रु.5100 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक ग्रेड	रु.6320 या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो

नोट-(i) किसी अधिकारी को न ली गयी चिकित्सा राशि को संचित (accumulate) करने की अनुमति होगी और इस प्रकार संचित राशि कभी भी ऊपर तालिका में दी गयी राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, या

(ii) वर्ष 2007 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति दो महीनों, अर्थात नवंबर 2007 और दिसंबर 2007 के लिए समानुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

व्याख्या- इस विनियम के उद्देश्य हेतु -

- (i) ऐसे मामलों में जहां अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, वहां स्टाफ सदस्य के मामले में हॉस्पिटलाइजेशन प्रभार का 100% तथा स्टाफ के परिवारिक सदस्य के मामले में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी या;
- (ii) 1 मई 2010 को और उस तारीख से इस विनियमन के अंतर्गत हॉस्पिटलाइजेशन व्यय की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारी हेतु द्विपक्षीय समझौते दिनांक 27.04.2010 में निर्धारित हॉस्पिटलाइजेशन के नियमों व शर्तों के अनुसार होगी। यह निम्न तालिका में निर्धारित की गई सीमाओं के अध्यधीन होगी।

"तालिका"

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I और मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II एवं III	<p>(i) बिस्तर प्रभार स्वयं - रु. 700 प्रति दिन परिवारिक सदस्य -रु. 525 प्रति दिन</p> <p>(ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों पर लागू हॉस्पिटलाइजेशन योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 125% की दर पर</p>
(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल IV एवं V और उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VI एवं VII	<p>(i) बिस्तर प्रभार स्वयं - रु. 900 प्रति दिन परिवारिक सदस्य - रु. 675 प्रति दिन</p> <p>(ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों पर लागू हॉस्पिटलाइजेशन योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 150% की दर पर</p>

9. कथित विनियमों के विनियम 25 में, उप- विनियम (2) के बदले, निम्नलिखित उप-विनियम होगा, अर्थात :

"(2) उप विनियम (1) में किसी बात के होते हुए, बैंक को इस बात का अधिकार होगा कि वह अधिकारी को रिहायिशी आवास उपलब्ध कराये, जिसके लिए अधिकारी, 1 नवंबर, 2007 को और उक्त तारीख से, वह जिस वेतनमान में है उसके पहले चरण मूल वेतन के 1.20% के बराबर राशि या मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, का भुगतान करेगा :

यदि ऐसे आवासों में जहां अधिकारी को फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है, तो बैंक द्वारा उस अधिकारी से, वह जिस वेतनमान में है उसके पहले चरण में मूल वेतन के 0.25% के बराबर की राशि वसूली जाए।

और जहां बैंक द्वारा ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है वहां बिजली, पानी, गैस और रखरखाव प्रभार का वहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

10. कथित विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम(2) के पश्चात, निम्न उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"(3) 1 मई 2010 से, 12 महीनों की कुल अवधि के अंतर्गत गर्भाशयोच्छेदन (hysterectomy) के मामले में अधिकतम 45 दिनों की छुट्टी भी प्रदान की जा सकती है।"

11. कथित विनियमों के विनियम 41 में, उप विनियम (4) में, खंड (ए) के बदले निम्नलिखित वाक्यांश होगा, अर्थात :

'(a) विराम भत्ता-1 मई 2010 से, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में दिये गये ग्रेड या स्केल में आने वाला अधिकारी इसके साथ कॉलम (2) में निर्धारित किये गये तदनुसूची दरों पर प्रति दिन के हिसाब से विराम भत्ता पाने का पात्र होगा। यथा :

"तालिका"

अधिकारी का ग्रेड/स्केल	बड़ी 'ए' वर्ग के शहर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
स्केल IV और ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
स्केल I/II/III के अधिकारी	800	700	600

बशर्ते यह कि स्केल IV और ऊपर वाले अधिकारियों में मामले में चार मेट्रो शहरों यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में कार्यालय से बाहर किसी काम के लिए विराम भत्ता रु. 1200 प्रति दिन के हिसाब से देय होगा और स्केल I या II या III के लिए प्रति दिन विराम भत्ता रु. 1000 होगा।

यदि बतायी गई अनुपस्थिति 8 घंटों से कम किंतु चार घंटे से अधिक हो तो, उपर्युक्त दरों की आधी दरों पर विराम भत्ता देय होगा।

व्याख्या : विराम भत्ते की गणना करने हेतु 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के किसी हिस्से को "प्रति दिन" माना जाएगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान हेतु रिपोर्टिंग टाइम और अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है वहां "प्रति दिन" का अर्थ उस अवधि से होगा जो आठ घंटों से कम की न हो।

12. कथित विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"(4) 1 मई, 2010 को और उक्त तारीख से, वह अधिकारी जो स्थानान्तरित हो, नीचे दी गई तालिका के अनुरूप पैकेजिंग, स्थानीय आवागमन, समान का बीमा करने आदि से संबंधित खर्चों के लिए एकमुश्त राशि आहरित करने का पात्र होगा :

"तालिका"

ग्रेड	एकमुश्त राशि
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 12,000
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 9,000

13. कथित विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल जोड़ा जाएगा, अर्थात :

" बशर्ते कि 1 मई 2010 से, कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I का अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय न्यूनतम किराये वाली इकोनॉमिक क्लास में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा। ऐसे मामले में वास्तविक किराए या की गयी यात्रा की दूरी हेतु, ए.सी. प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराए, इनमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और यही नियम 1000 किमी से कम दूरी के लिए अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III के अधिकारी पर भी लागू होगा।

14. कथित विनियमों के विनियम 45 में -

- (i) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात :

" बशर्ते यह कि 1 अप्रैल, 2010 को और उक्त तारीख से बैंक की सेवा में नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए कोई भी भविष्य निधि उपलब्ध नहीं होगी।"

- (ii) उप-विनियम (3) में, खंड (बी) के बाद और नोट से पूर्व, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात :

"(सी) जो अधिकारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल है, और जिन्होंने पेंशन योजना के विकल्प का चयन नहीं किया है, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जारी रह सकते हैं।";

- (iii) उप-विनियम (3), के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा :—

"1 अप्रैल 2010 को अथवा उसके बाद बैंक में सेवारंभ करने वाले अधिकारियों की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत शामिल किया जाएगा, जहाँ भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ. नं. 5/7/2003-ईसीबी एण्ड पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003, समय-समय पर यथा संशोधित, के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के अनुरूप अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसरण में संबंधित अधिकारी मंहगाई भत्ता सहित अपने वेतन के 10% का अंशदान करेगा और बैंक भी उसके समान राशि का अंशदान करेगा।"

15. कथित विनियमों की अनुसूची के बदले, निम्नलिखित अनुसूची होगी:-

"बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारियों) सेवा विनियम 1979 की अनुसूची"

[विनियम 23 के उप-विनियम (2) देखें]

1 नवंबर, 2017 से प्रभावी कोई अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक उसमें पूर्ण या आंशिक आशोधन नहीं किया जाता, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका में निर्दिष्ट है:—

तालिका

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम वेतन	रु.14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
1.	मिज़ोरम (ए) मिज़ोरम का चिमतुईपुई जिला और ऐसे क्षेत्र जो मिज़ोरम के लुंगलेई जिले में लुंगलेई कस्बे से 25 किमी से अधिक दूरी पर हों	2000	2600
	(बी) मिज़ोरम के लुंगलेई कस्बे से 25 किमी से ज्यादा दूर स्थित क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला	1600	2100
	(सी) मिज़ोरम का पूरा ऐजावल जिला	1200	1500
2.	नागालैण्ड	1600	2100
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप (ए) उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नारकोनडम द्वीप (बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर को मिलाकर)	2000 1600	2600 2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप	2000	2600
6.	असाम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा (ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र (बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरा त्रिपुरा	1600 1200	2100 1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश (ए) अरुणाचल प्रदेश का कठिन क्षेत्र (बी) अन्य जटिल क्षेत्रों को छोड़कर पूरा अरुणाचल प्रदेश	2000 1600	2600 2100
11.	जम्मू और कश्मीर (ए) कठुआ जिला : नियाबत बानी, लोही, मल्हार और माछोडी	2000	2600
	(बी) उधमपुर जिला : डूङ बसंतगढ़, लंदर भमग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल क्षेत्र छोड़कर मोहरे तहसील में लम्बन क्षेत्र से गोयल क्षेत्र तक और कैसी क्षेत्र से अरनास क्षेत्र तक	2000 1600	2600 2100
	(सी) डोडा जिला : किश्तवार तहसील में पदेर और निबत नौगम के इलाके	2000	2600
	(डी) लेह जिला : जिले में सभी स्थान	2000	2600
	(ई) बारामूल्ला जिला: (i) पूरा गुरेज-निराबत, तंगदार सब-डिवीजन और केरन इलाका	2000	2600

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम वेतन	रु.14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
	(ii) मचिल (एफ) पूछ और राजौरी जिला : पूछ और राजौरी शहर छोड़कर पूछ और राजौरी के क्षेत्र तथा सुंदरबनी और दोनों जिलों के अन्य शहर (जी) उपरोक्त (ए) से (एफ) में जो क्षेत्र शामिल नहीं हैं, लेकिन जो वास्तव में नियंत्रण रेखा से 8 किमी के अंतर्गत हैं अथवा ऐसे स्थल जो राज्य सरकार द्वारा अपने स्टाफ के लिए समय-समय पर बोर्डर भत्ते के लिए अर्हक क्षेत्र घोषित किए गए हों।	1600 1200 1200	2100 1500 1500
12.	हिमाचल प्रदेश (ए) चम्बा जिला (i) पांगी तहसील, भरमोर तहसील, पंचायत : बडगांव, बजौल, देओल कुगटी, नयागाम और टुंडाह, ग्राम : जगत ग्राम पंचायत का घाटू, चहाता ग्राम पंचायत का कनारसी (ii) भरमोर तहसील उपरोक्त (i) मद में दिये गये पंचायत और गांवों को छोड़कर। (iii) भतियात तहसील में झंड़ू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बानीखेत प्रौपर को मिलाकर)	2000 1600 1200	2600 2100 1500
	(बी) किन्नौर जिला (i) असरंग, चितकुल और हांगो कुनो/चारंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र में छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायत, पूह उप-खंड, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर (ii) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला (सी) कुल्लू जिला : (i) निरमांड तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें खारगा, कुश्वर और सारगा ग्राम पंचायत शामिल हैं। (ii) आउटर-सराज (निर्मांड तहसील में जकात-खाना और बुरो गाँव छोड़कर) और सम्पूर्ण जिला, आउटर-सराज और पंद्रहबीस का परगना छोड़कर, लेकिन तहसील निमांड के बुरो और जगत-खाना गावों को मिलाकर (डी) लाहौल और स्पीति जिला : लाहौल और स्पीति का पूरा क्षेत्र (ई) शिमला जिला : (i) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लावना सदाना, सरपारा और चडी-बरांडा पंचायत शामिल हैं	2000 1600 2000 1200 2000 2000	2600 2100 2600 1500 2600 2600
	(ii) दोरा-कवर तहसील, रामपुर में दरकली ग्राम पंचायत, कशपथ तहसील और मुनीश, परगना सराहन की घोरी चैंबिस। (iii) चोपाल तहसील और घोरिस, पंजगांव, पटसनौ, नौबिस और परगना सराहन की तीन कोठी, तकलेश क्षेत्र की देओथी ग्राम पंचायत, परगना बराबिस रामपुर तहसील का रामपुर कस्बा और परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला कस्बा और उसका नगर परिसर (धाली, जतोग, कसुम्पति, मशोब्रा, तारादेवी और टूटू)	1600 1200	2100 1500

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम वेतन	रु.14,700/- से अधिक वेतन
1	2	3	4
	(एफ) कांगड़ा जिला :		
	(i) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र	1600	2100
	(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला कस्बा और नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कस्बे लेकिन धर्मशाला कस्बे में शामिल-विमेन्स आईटीआई, दारी, मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, शिशु कल्याण और शहर एवं देश आयोजना कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, दूगैर, एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर, आंचलिक (जोनल) मलेरया कार्यालय, दारी वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, दारी, आई.पी.एच. उप-खण्ड, दान, निपटान (सेटलमेंट) कार्यालय, शामनगर, हिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर। पालमपुर के एचपीकेवीवी कैम्पस को मिलाकर कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर और नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय लेकिन पालमपुर शहर में शामिल-एच.पी.कृषि विश्व-विद्यालय कैम्पस, मवेशी विकसित कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि वर्कशॉप/एचपीपीडब्ल्यूडी प्रभाग, बुंदला, इलेक्ट्रिकल उप-खंड, लोहना, डी.पी.ओ. निगम, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई खंड, घुग्गर।	1200	1500
	(जी) मण्डी जिला :		
	जोगिन्दर नगर तहसील की छहार वैली, बग्गा, चन्नी, छोटधर, गरागुशैम, गाढ़, गरयास, जन्मेहली, जरयार, जोहर, कल्हानी, कल्वां, खोलनल, लोथ, सिलिबागी, सोमाचन, थच्छर, टाची, थाना की पंचायतें सुनाग तहसील में, धर्मपुर ब्लॉक-बिंगा, कमलाह, सकलाना, टनयार और लाराखोलाह की पंचायतें, करसोग तहसील-बालीधर, बग्गा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुडी, मांज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन की पंचायतें, सुंदरनगर तहसील-बोही, बटवारा, धान्यारा, पौराकोठी, सेरी और शौजा।	1200	1500
	(एच) सिरमौर जिला :		
	बानी, बखाली (पठड तहसील), भारोग भेनेरी (पैनता तहसील), बिरला (नहान तहसील), दिब्बेर (पछड़ तहसील) और थाना कलौगा (नाहन तहसील) और थानसगीरी भूभाग की पंचायतें।	1200	1500
	(आई) सोलन जिला :		
	मंगल पंचायत	1200	1500
	(जे) उपरोक्त (ए) से (आई) तक की मदों में शामिल नहीं किए गए हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र	320	400
13.	उत्तराखण्ड चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चम्पावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।	2000	2600

व्याख्यात्मक ज्ञापन

जिन विनियमों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी किया गया था वे इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए निर्दिष्ट अध्यादेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ एवं शीर्ष स्तर पर बैंकों के अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के सहमत निबंधन एवं शर्तों के अनुसार हैं।

एम के गुप्ता
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

नोट : मुख्य विनियम भारत के गज़ट में दिनांक _____ को प्रकाशित हुआ था और उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित हुई, यथा :-

क्र. संख्या	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	51	17.12.1988
2.	11	17.03.1990
2.	8	23.02.1991
3.	18	02.05.1992
4.	34	23.08.1997
5.	21	22.05.1999
6.	14	01.04.2000
7.	3	20.01.2001
8.	39	29.09.2001
9.	21	24.05.2003
10.	103	28.06.2006
11.	186	16.12.2006

दिनांक 10 जनवरी 2018

सं. HO:TBD:2878.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) ये विनियम बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम 2017 कहलाएंगे।
 - (2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में (इसके बाद कहे गये विनियमों के रूप में संदर्भित), -

विनियम 2, के खंड (एस) में उपखंड (सी) के बाद निम्नांकित उप खंड जोड़ा जाए, अर्थात् :-

(डी) मई 2005 के प्रथम दिवस या उसके बाद सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त या मृत्यु होने पर किसी कर्मचारी के संबंध में, बैंक में अपनी सेवा के पिछले दस महीनों के दौरान कर्मचारी द्वारा आहरित, नियत वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन, यदि कोई हो, और विशेष वेतन, स्नातक वेतन, व्यावसायिक योग्यता वेतन, नियत कार्मिक वेतन का वेतन वृद्धि घटक और स्थानापन्न वेतन, यदि कोई हो, परंतु 01 मई 2005 से प्रभावी इस खंड के प्रावधानों में अप्रैल 1998 के प्रथम दिवस पर या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 से पहले सेवा में सेवानिवृत्त या मृत्यु हो जाने वाले किसी कर्मचारी के संबंध में प्रभाव पड़ेगा।
- उक्त विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(4) (क) अधिसूचित तिथि के बाद और 31 मार्च 2010 को या उससे पहले बैंक की सेवा में सेवारत हो.”

(ख) उप-विनियम 10 के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् :-

 - (11) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे और 27 अप्रैल 2010 तक बैंक की सेवा में सेवारत रहे हों, बशर्तकि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;
 - (12) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे तथा उस तिथि से और 27 अप्रैल 2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों, बशर्तकि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;
 - (13) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए और मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;

(14) जो बैंक की सेवा में 29 सितंबर 1995 से पहले थे, और उस तिथि के बाद बैंक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार, पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;

4. उक्त विनियमों के विनियमन 28 में, प्रावधानों के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण 29 सितम्बर 1995 को या उसके बाद सेवा में नहीं थे, लेकिन 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत इस संबंध में बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार एवं सरकार द्वारा अनुमोदित, योजना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन पेंशन फंड में शामिल होने के हकदार होंगे।"

5. उक्त विनियमों के विनियमन 36 में, -

(क) खंड (सी) में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु 1 मई 2005 को, या से, अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके पश्चात, परंतु 31 अक्टूबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए, उनकी न्यूनतम पेंशन एक हजार साठ रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके बाद, सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की तीन सौ पचपन रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की पाँच सौ तीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ पंचानवे रुपये प्रतिमाह होगी।

(ख) खंड (सी) के बाद निम्नलिखित खंड (डी) शामिल किया जायेगा, अर्थात् :-

(डी) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार चार सौ पैंतीस रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की चार सौ अस्सी रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ बीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार अस्सी रुपये प्रतिमाह होगी।

परंतु 1 मई 2005 के प्रथम दिवस से, इस खंड के प्रावधान अंशकालिक कर्मचारी सहित किसी भी कर्मचारी पर लागू होंगे, जो 1 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए।

(ई) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो नवम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार सात सौ उन्चासी रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो नवम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की पाँच सौ पंचानवे रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की आठ सौ बानबे रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार तीन सौ उन्तालिस रुपये प्रतिमाह होगी।

6. उक्त विनियमों के विनियम 40 के उप-विनियम (4) में,-

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (III) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

'परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों "छह हजार सात सौ छप्पन" को शब्द "सात हजार और चालिस" से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैंसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

'परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों "छह हजार सात सौ छप्पन" को शब्द "सात हजार और चालिस" से प्रतिस्थापित किया गया है।

- (iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैंसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;
- (v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;
- (iii) खंड (सी) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-
 'परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसे कि शब्दों "तीन हजार तीन सौ अठत्तर" को शब्द "तीन हजार पाँच सौ बीस" से प्रतिस्थापित किया गया है।
- (iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल चार हजार सात सौ तिरासी रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;
- (v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल पाँच हजार नौ सौ अठ्ठाइस रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये
7. उक्त विनियमों के विनियम 48 में, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 "48. बैंकों को हुई आर्थिक हानि की वसूली.-
 (1) यदि पेंशनभोगी अपनी सेवा की अवधि के दौरान किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में घोर कदाचार या लापरवाही या आपराधिक न्यासभंग या जालसाजी या कपटपूर्ण कार्य का दोषी पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसका अंश रोक सकता है या आहरित कर सकता है, चाहे स्थायी रूप से या निर्धारित अवधि के लिये, और बैंक को हुई किसी भी आर्थिक हानि के पूरे या अंश को पेंशन से वसूल करने के आदेश दे सकता है।
 परंतु कोई भी अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जायेगा।
 परंतु जहां पेंशन के एक अंश रोक दिया गया है या आहरित किया गया है, पेंशनभोगी द्वारा आहरित पेंशन की रकम इन विनियमों के तहत देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी।
 परंतु यह भी कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात, विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी की सेवा में रहते हुए आरंभ की गई है, इन विनियमों के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी तथा प्राधिकारी द्वारा वह आरंभ की गई थी वह उसी प्रकार से जारी रखी जायेगी तथा समाप्त की जायेगी मानो कर्मचारी सेवा में है।
- (2) यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी, तो ऐसे संस्थापन के चार वर्ष पूर्व हुई किसी भी घटना के मामले में कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जायेगी।
 परंतु इस प्रकार आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही, कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही के लिये लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी।
- (3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है वहाँ वसूली सामान्यता कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जायेगी।
8. उक्त विनियमों के विनियम 52 में:-
 (ए) उप-विनियमन (1) के लिये, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 "(1) किसी कर्मचारी के संबंध में जहां विनियम 34 या विनियम 46 के प्रावधान लागू होते हैं, परिवार की पेंशन के अलावा एक पेंशन उस तारीख से देय होगी, जिस पर कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है।"
- (बी) उप-विनियम (3) में निम्न प्रावधान को शामिल किया जायेगा:-
 "परंतु 27 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने वाले को परिवार पेंशन सहित पेंशन 27 नवंबर 2009 से लागू होगी।"
9. उक्त विनियम के परिशिष्ट II में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 परिशिष्ट II
 (विनियम 37 देखें)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित अनुसार होगी :-

- (1) अधीनस्थ श्रेणी के जो कर्मचारी, 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात, परंतु 01 नवंबर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात परंतु 01 जुलाई 1993 के पूर्व

सेवानिवृत्त हुए थे, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर, यथास्थिति 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 1250/- तक	0.67 प्रतिशत
(ii) रु. 1251/- से रु. 2000/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 1250/- से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत
(iii) रु. 2001/- से रु. 2130/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा रु. 2000/- से अधिक मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत।
(iv) रु. 2130/- से अधिक	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- और रु. 2000/- के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत।
(2) कामगार श्रेणी के जो कर्मचारी 01 नवंबर 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जुलाई 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर, यथास्थिति, प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :	

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 2400/- तक	0.35 प्रतिशत
(ii) रु. 2401/- से रु. 3850/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 2400/- से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत।
(iii) रु. 3851/- से रु. 4100/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत + रु. 3850 से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत।
(iv) रु. 4100/- से अधिक	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- और रु. 3850/- के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत।
(3) जो कर्मचारी 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1616 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी ::—	

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 3380/- तक	0.25 प्रतिशत
(ii) रु. 3381/- से रु. 5420/-	रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 3380/- से अधिक मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत।
(iii) रु. 5421/- से रु. 5770/-	रु. 3380/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत + रु. 5420 से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत।
(iv) रु. 5770/- से अधिक	रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत तथा + रु. 5770/- और रु. 5420/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 5770/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत।

परंतु, 1 मई 2005 पर या से कर्मचारियों के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात लेकिन 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1684 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :-

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 3550/- तक	0.24 प्रतिशत
(ii) रु. 3551/- से रु. 5660/-	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 3550/- से अधिक मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत।
(iii) रु. 5651/- से रु. 6010/-	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत + रु. 5650 से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत।
(iv) रु. 6010/- से अधिक	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत तथा + रु. 6010/- और रु. 5650/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 6010/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत।

- (4) 1 मई 2005 पर या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.18 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी:-

परंतु 1 मई 2005 पर या से, कर्मचारियों के संबंध में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, महंगाई राहत इस खंड की शर्तों के अनुसार देय होगी :

परंतु 1 नवंबर 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.15 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी:-

- (5) महंगाई भत्ता पिछले वर्ष के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर पहली फरवरी से आरंभ और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिये और उसी वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर और 01 अगस्त से आरंभ और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिये देय होगा।
- (6) परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन और अनुकम्पा भत्ते के संबंध में महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार देय होगी।
- (7) पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राशि की अनुमति संराशीकरण के बाद भी दी जायेगी।
- (8) महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर देय नहीं हैं।
- (9) जिस पेंशनभोगी की मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है परंतु मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है, वह न्यूनतम पेंशन पर लागू महंगाई राहत आहरित कर सकेगा।
10. उपरोक्त विनियमों में परिशिष्ट III के लिये निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट III

(विनियम 39 देखें)

परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :-

- (क) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी कामगार श्रेणी में था और 01 नवम्बर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था या जहाँ कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 01 जुलाई 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था:-

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात परंतु 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :—

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 4210 तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1056/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु. 4211 से रु. 8420	'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1262/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु. 8420 से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1687/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 3521/- प्रतिमाह होगा।

(घ) 01 मई 2005 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में:—

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 5720 तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1435/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु. 5721 से रु. 11440	'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1715/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु. 11440 अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2292/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 4784/- प्रतिमाह होगा।

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके पश्चात परंतु 30 अप्रैल 2005 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस खंड के अनुसार निम्न होंगी :—

(च) 01 मई 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में:—

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 7090 तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1779/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।

- रु. 7091 से रु. 14180 'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2186/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
- रु. 14180 से अधिक 'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2841/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 5930/- प्रतिमाह होगा।

टिप्पणी :—

- (1) महंगाई भत्ता अतिरिक्त परिवार पेंशन पर देय नहीं होगा।
- (2) उपर्युक्त अनुसार परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन से वेतनमान, विनियम 2 के उप खंड (एस) में निर्धारित 'वेतन' तथा विनियम 35 के उप-विनियम (3) की व्याख्या में निर्धारित भत्तों का योग होगा
- (3) अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम राशि, कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन की दर के अनुपात में होगी।
- (4) यदि मूल परिवार पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का कुल योग न्यूनतम पेंशन से कम होता है तो पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन दी जाए और ऐसी न्यूनतम परिवार पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। लेकिन, न्यूनतम परिवार पेंशन के अतिरिक्त परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पूर्वव्यापी प्रभाव से दिए गए उक्त विनियमों को संयुक्त नोटों और निपटान के लिये सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार, संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तर के कामगार संघों तथा अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित है। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एम. के. गुप्ता
महाप्रबंधक
मानव संसाधन विभाग

BANK OF INDIA

The 12th September 2017

No. BOI/HO/HR/IR/MSS/L-234.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the BANK OF INDIA, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,—

- (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation.—For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs. 3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs. 3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’

- (ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,—

- (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;
- (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

- (a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs. 46800—1300/4 — 52000

Scale VI = Rs. 42000—1200/4 — 46800

- (b) Senior Management Grade

Scale V = Rs. 36200—1000/238200—1100/2 — 40400

Scale IV = Rs. 30600—900/4—34200/1000/2 — 36200

- (c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 25700—800/5—29700—900/2 — 31500

Scale II = Rs. 19400—700/1—20100 -800/10 — 28100

- (d) Junior Management Grade

Scale I = Rs. 14500—600/7—18700—700/2—20100—800/7—25700.

Explanation.—Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, —

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: —

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: —

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs. 800 each and next two Rs. 900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.—Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

- (b) in sub-regulation (2),—

- (i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:—

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs. 1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

- (ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—
“(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;
- (c) in sub-regulation (3),—
(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—
“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:—

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”,

- (ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:—
“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.
(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;
(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:—
“(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations,—

- (i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;
(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;
(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:—
“(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.
Explanation.—For the purposes of this sub-regulation,—
(a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;
(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

- “(1) on and from the 1st day of November, 2002,
(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

- (2) on and from the 1st day of November, 2007,—

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.—The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,—

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—
- “(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs. 290 per month or Rs. 255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
- (4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs. 2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month.”;

- (iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs. 165 per month.”;

- (v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November, 2007” shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs. 680 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs. 1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:—

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 6320 or the amount incurred whichever is less

Note.— (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

- (ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation.—for the purposes of this regulation,-

- (i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;
- (ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self –Rs. 700 per day Family–Rs. 525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self –Rs. 900 per day Family–Rs. 675 per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

“(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(a) Halting Allowance—On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Grades/Scales of officers	Major ‘A’ Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs. 1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs. 1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.—For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours. ’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:—

“TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs. 12,000
Middle Management and Junior Management	Rs. 9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule to Bank of India (Officers’) Service Regulations, 1979

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
1.	Mizoram		
	(a) Chimpui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	(a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:		
	(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District		
	(i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(a) Chamba District		
	(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram	2000	2600

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.		
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(c) Kullu District: (i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Saraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District : (i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District: (i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town—H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil-Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil-Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(i) Solan District : Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13.	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

M. K. GUPTA
General Manager (HR)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India on _____ and subsequently amended vide following notifications, namely:—

Sr. No.	Notification No.	Date
1.	51	17.12.1988
2.	11	17.03.1990
2.	8	23.02.1991
3.	18	02.05.1992
4.	34	23.08.1997
5.	21	22.05.1999
6.	14	01.04.2000
7.	3	20.01.2001
8.	39	29.09.2001
9.	21	24.05.2003
10.	103	28.06.2006
11.	186	16.12.2006

The 10th January 2018

No. HO:TBD:2878.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bank of India (Employees') Pension Regulations 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), -
In regulation 2, in clause (s), after sub-clause(c), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
“(d) in relation to an employee who retired or died while in service on or after the first day of May, 2005 the basic pay including stagnation increments, if any, and Special Pay, Graduation Pay, Professional Qualification Pay, increment component of Fixed Personnel Pay and Officiating Pay, if any, drawn by the employee during the last ten months of his service in the Bank:

Provided that with effect from 1st day of May, 2005 the provisions of this clause shall have effect in relation to an employee who retired or died while in service on or after 1st day of April, 1998 but before 30th day of April, 2005.”.
3. In regulation 3 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
“(4) (a) join the service of the bank on or after the notified date and on or before the 31st day of March, 2010;”.
(b) after sub-regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-
“(11) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and continue in the service of the Bank as on the 27th April, 2010 provided such employee meets the requirement and comply with the conditions laid down in the settlement;
(12) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and retired after that date and prior to 27th April, 2010 provided such employee meets the requirements and comply with the conditions laid down in the settlement;
(13) wherein service of the Bank, prior to the 29th September, 1995 retired after that date and had died in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meets the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement;
(14) were in the service of the bank prior to the 29th September, 1995 and died while in service of the Bank after that date in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meet the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement.”.
4. In regulation 28 of the said regulations, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided further that employees who ceased to be in service on or after the 29th September, 1995 on account of voluntary retirement before attaining the age of superannuation but after rendering service for a minimum period of 15 years in accordance with the Scheme framed in this regard by the Board with the approval of the Government, shall be entitled to join the Pension Fund, subject to the compliance of the terms and conditions mentioned in the Scheme.”.
5. In regulation 36 of the said regulations,-
(a) in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that on and from the 1st day of May, 2005 the amount of minimum pension, in respect of an employee, other than a part-time employee, who retired on or after the 1st April, 1998 but before the 31st October, 2002 shall be rupees one thousand and sixty per month and rupees three hundred and fifty five in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale wages, rupees five hundred and thirty in respect of a part-time employee drawing ½ scale wages and rupees seven hundred and ninety five in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after 1st day of April, 1998.”;

- (b) after clause (c), the following clause (d) shall be inserted namely:—

“(d) rupees one thousand four hundred and thirty five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of May 2005 and rupees four hundred and eighty per month in respect of a part-time employee drawing $\frac{1}{3}$ scale of wages, rupees seven hundred and twenty per month in respect of part-time employee drawing $\frac{1}{2}$ scale wages and rupees one thousand and eighty per month in respect of a part-time employee drawing $\frac{3}{4}$ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of May 2005:

Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this clause shall also apply to an employee including a part-time employee who retired on or after 1st November 2002 but on or before 30th April 2005.;

- (e) rupees one thousand seven hundred and seventy nine per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of November 2007 and rupees five hundred and ninety five per month in respect of a part-time employee drawing $\frac{1}{3}$ scale of wages, rupees eight hundred and ninety two per month in respect of part-time employee drawing $\frac{1}{2}$ scale of wages and rupees one thousand three hundred and thirty nine per month in respect of a part-time employee drawing $\frac{3}{4}$ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November 2007.”.

- (6) In regulation 40, of the said regulations, in sub-regulation (4),-

- (i) in clause (a), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:—

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “six thousand seven hundred and fifty six”, the words “seven thousand and forty”, had been substituted.;

- (iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005. ’;

- (v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.”

- (ii) in clause (b), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:—

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “six thousand seven hundred and fifty six”, the words “seven thousand and forty”, had been substituted;

- (iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005. ’;

- (v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

- (iii) in clause (c), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:—

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “three thousand three hundred and seventy eight,” the words “three thousand five hundred and twenty,” had been substituted.;

- (iv) four thousand seven hundred and eighty three rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005. ’.

- (v) five thousand nine hundred and twenty eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

- (7) For regulation 48 of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely:—

“48. Recovery of pecuniary loss caused to Bank.—

- (1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or for acts done fraudulently during the period of his service:

Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations:

Provided also that the departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service.

- (2) No departmental proceedings, if not instituted while the employee was in service, shall be instituted in respect of an event which took place more than four years before such institutions:

Provided that the disciplinary proceedings so instituted shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

- (3) Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of the employee.”.

8. In regulation 52 of the said regulations,-

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 34 or regulation 46 apply, a pension other than family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires.”.

- (b) in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that pension including family pension to those who opted to join the Bank Employees’ Pension Scheme on or after the 27th April, 2010 shall be payable with effect from the 27th November, 2009.”.

9. For Appendix II to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely:-

“Appendix II

(See regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under :-

- (1) In the case of employees who were in the workmen cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who were in the officers’ cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:-

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)
(i) Upto Rs. 1250	0.67 per cent
(ii) Rs. 1251 to Rs. 2000	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs. 1250.
(iii) Rs. 2001 to Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs. 2000.
(iv) Above Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs. 2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130.

- (2) In the case of employees who are in workmen cadre and who retire on or after the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who are in the officers’ cadre and who retire on or after the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)
(i) Upto Rs. 2400	0.35 per cent
(ii) Rs. 2401 to Rs. 3850	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs. 2400
(iii) Rs. 3851 to Rs. 4100	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 3850

- (iv) above Rs. 4100 0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs. 4100 and Rs. 3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs. 4100
- (3) In the case of employees who retire on or after the 1st day of April, 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—
- | Scale of basic pension per month
(1) | The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(2) |
|---|--|
| (i) Upto Rs. 3380 | 0.25 per cent |
| (ii) Rs. 3381 to Rs. 5420 | 0.25 per cent of Rs. 3380 plus 0.21 per cent basic pension in excess of Rs. 3380 |
| (iii) Rs. 5421 to Rs. 5770 | 0.25 per cent of Rs. 3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs. 5420 and Rs. 3380 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs. 5420. |
| (iv) Above Rs. 5770 | 0.25 per cent of Rs. 3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs. 5420 and Rs. 3380 plus 0.12 per cent of the difference between Rs. 5770 and Rs. 5420 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs. 5770. |

Provided that on or from the 1st day of May 2005 in the case of employees who retire on or after the 1st day of April 1998 but on or before the 31st October 2002, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner given below:

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i) UptoRs. 3550	0.24 per cent
(ii) Rs. 3551 to Rs. 5650	0.24 per cent of Rs. 3550 plus 0.20 per cent basic pension in excess of Rs. 3550
(iii) Rs. 5651 to Rs. 6010	0.24 per cent of Rs. 3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs. 5650 and Rs. 3550 plus 0.12 of basic pension in excess of Rs. 5650
(iv) Above Rs. 6010	0.24 per cent of Rs. 3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs. 5650 and Rs. 3550 plus 0.12 per cent of the difference between Rs. 6010 and Rs. 5650 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs. 6010

- (4) In respect of employees who retire on or after the 1st day of May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after 1st day of November 2002 but on or before 30th day of April 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2007, Dearness Relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent of basic pension.

- (5) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with the 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

- (6) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.
- (7) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.
- (8) Dearness relief is not payable on additional pension.
- (9) Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.”.

10. For Appendix III to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely :-

“Appendix III

(See Regulation 39)

The ordinary rates of family pension shall be as under:-

- (a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired before the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers’ cadre and retired before the 1st day of July, 1993:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs. 1500	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 375 per month.
Rs. 1501 to Rs. 3000	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 450 per month.
Above Rs. 3000	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 600 per month and not more than Rs. 1250 per month.

- (b) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired on or after the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers’ cadre and retired on or after the 1st day of July 1993:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Upto Rs. 2870	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 720 per month.
Rs. 2871 to Rs. 5740	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 860 per month.
Above Rs. 5740	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1150 per month and a maximum of Rs. 2400 per month.

- (c) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of April, 1998: —

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
UptoRs. 4040	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 1015 per month.
Rs. 4041 to Rs. 8080	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 1212 per month.
Above Rs. 8080	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 1616 per month and a maximum of Rs. 3378 per month:
Provided that on and from the 1st day of May, 2005 in respect of the employees (both officers and workmen), other than part time employees, who retired on or after the 1st day of April 1998 but on or before the 31st day of October, 2002, the ordinary rate of family pension shall be as under:-	

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Up to Rs. 4210	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1056 p.m.
Rs. 4211 to Rs. 8420	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1262 p.m.
Above Rs. 8420	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1687 p.m. and a maximum of Rs. 3521 p.m.

- (d) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of the May 2005:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Upto Rs. 5720	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1435 p.m.
Rs. 5721 to Rs. 11440	20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 1715 p.m.
Above Rs. 11440	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 2292 p.m. and maximum of Rs. 4784 p.m.

Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2002 but on or before the 30th April 2005, ordinary rates of family pension shall be in terms of this clause.

- (e) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November 2007:—

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
Upto Rs. 7090	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1779 p.m.
Rs. 7091 to Rs. 14180	20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs. 2186 p.m.
Above Rs. 14180	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 2841 p.m. and maximum of Rs. 5930 p.m.

Notes :—

- (1) Dearness relief is not payable on additional family pension.
- (2) Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of Pay as defined in clause (s) of regulation 2 and allowances as defined in the Explanation to sub-regulation (3) of regulation 35.
- (3) In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.
- (4) In case the aggregate of basic family pension and additional family pension falls short of minimum pension the pensioner may be given minimum family pension and dearness relief may be paid on such minimum family pension. However, no additional family pension shall be payable over and above the minimum family pension.”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks’ Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers’ associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

M. K. GUPTA
General Manager (HR)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2018
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2018

www.dop.nic.in